an>

Title: Regarding alleged atrocities by village chiefs in Uttar Pradesh.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में 62 हजार ग्राम पंचायतों से संबंधित अति महत्वपूर्ण मुद्दा शून्यकाल में उठाने की आपने अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैडम, प्रधानमंत्री जी द्वारा गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए 14वें वित्त आयोग में भारत सरकार द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में धनराशि देने की व्यवस्था की गयी है, जिससे गांव के लोग स्वयं तक कर सकें कि कहां पर किन चीजों की एवं विकास के किस कार्य की जरूरत है और गांव का समग्र विकास हो सके। पहले ग्राम प्रधानों द्वारा बनाई गयी कार्ययोजना की आईडी ब्लॉकस्तर पर बनाई जाती थी। ब्लॉक स्तर पर बनाने की व्यवस्था थी जिससे कार्य कराने में सुविधा होती थी, परंतु 14वें वित्त आयोग से जो भी विकास कार्य की योजना बनाई जा रही है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर पर आई.डी. बनाने का आदेश दिया गया है, जिससे आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी ग्राम पंचायत की आई.डी. न बनने के कारण 14वें वित्त आयोग से एक रुपये का भी विकास कार्य नहीं हो पाया है।

मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद कौशाम्बी में जिला प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि ग्राम पंचायत स्वयं कार्य न कराकर जिला प्रशासन द्वारा बनायी गयी किसी नामी संस्था या एन.जी.ओ. द्वारा कार्य कराया जाए जबकि ग्राम पंचायत स्वयं में एक कार्यदायी संस्था है। मैं माननीय ग्रामीण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसमें तत्काल हस्तक्षेप करें और प्रदेश सरकार को दिशानिर्देश जारी करें कि 14वें वित्त आयोग की धनराशि से पूर्व की भांति ब्लॉक से आई.डी. बनाने की अनुमति दे जिससे केवल ग्राम पंचायतों को कार्य कराने का अधिकार रहे। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Ajay Misra Teni are permitted to associate with the issue raised by Shri Vinod Kumar Sonkar.